Indian J. Soc. & Pol. 09 (02) : 87-90: 2022 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
First Published Online 31 JULY 2022 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

अटल बिहारी वाजपेयी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार : एक अध्ययन

अखिलेश्वर शुक्ला[1], अमृता दूबे[2]

[1]विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0 भारत
[2]शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग,राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

आधुनिक भारत के स्वर्णिम निर्माणकाल के स्वप्न द्रष्टा शारदा के वरद् हस्त् पुत्र, राजनेता विचारक "अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसम्बर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिंदे की छावनी में हुआ था। जहाँ उनके जीवन पर समाज की विविध घटनाओ के साथ–साथ राजनीतिक घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा, जिसने अटल जी को एक विचारक की पंक्ति में ला खड़ा किया यद्यपि वह सदैव एक राजनेता ही रहे। अटल जी का यह वैचारिक समृद्धि मूलतः से अपने पिता पं. कृष्ण बिहारी वाजपेयी से प्राप्त हुई थी क्योंकि वह अध्यापक होने के साथ–साथ एक कुशल लेखक भी थे जिसका प्रभाव अटल जी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अटल जी ने मात्र एक राजनेता की भूमिका नहीं निभायी वरन् एक दार्शनिक की तरह समाज के हर मुद्दे पर अपनी एक मौलिक विचार दृ ष्टि प्रस्तुत की। उनके विचारो की उत्कृष्टता आज के सन्दर्भ में भी उपयोगी है।

KEYWORDS: *राष्ट्रवाद, मानववाद, राजनीतिक विचारक, अटल विहारी बाजपेयी*

अटल जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा एक अपरिहार्य तत्व है अतः यह आवश्यक है कि समाज का कोई भी वर्ग शिक्षा से वंचित न हो सभी को शिक्षा प्राप्ति का समुचित अवसर मिले। सन 2001 में जब अटल जी अपने प्रधानमन्त्री शासन काल ने सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत की जिसका चर्चित गीत 'स्कूल चलें हम' अटल जी ने स्वयं लिखा था। अटल बिहारी बेहतर शिक्षा व्यकवस्था के लिए प्रतिवद्ध थे। तथा वे केरल में श्रीनारायण गुरू द्वारा संचालित शिक्षा व्यथवस्था से अत्यन्त प्रभावित भी थे अतः वे नई पीढ़ी को मात्र ज्ञान के लिए नही जीवन के लिए शिक्षा देना चाहते थे। क्योंकि ज्ञान मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं की रक्षा करने राष्ट्र के प्रति दायित्व निर्वह्न व स्वयं के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक है भारत स्वतन्त्रता संघर्ष के पश्चात अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति से निकल कर आगे बढ़ा अतः आवश्यक है कि आज हम ऐसी सुदृढ़ शिक्षा पद्धति की स्थापना करे जो मात्र हमे शिक्षित न करे वरन् जीवन प्रदान करे जीविकोपार्जन के योग्य बनाए जहां आधुनिक के साथ–साथ प्राचीन वेद, उपनिषद का ज्ञान भी मौजुद हो, परहित को मनुष्य अपना धर्म समझ कर कार्य करे जिससे समाज में व्याप्त वैमनस्य समाप्त हो सके। अतः अटल बिहारी ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया और प्रधानमंत्री बनकर उनके इस कार्य को पूर्णता प्राप्त हो सकी। एक कवि कैसे शिक्षा के अभाव में दुश्वारियां झेलते बच्चों को उनके जीवन से वंचित देखता अतः उन्होंने सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से सभी को स्कूल भेजने का जिम्मा स्वयं उठाया जो आम जनमानस व निर्धन वर्ग के लिए विशेषकर लाभदायक सिद्ध हुई। इसका उद्देय शिक्षा के बुनियादी ढ़ांचे में सुधार कर शिक्षा का समावेशीकरण करना था जिससे समाज के आखिरी पायदान तक शिक्षा पहुँच सके। यह अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो लागू होने के चार साल के भीतर ही अपनी सफलता का दिग्दर्शन करा दिया। "स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या जो 2001 में 32 करोड़ थी वह 2005 में घटकर मात्र 95 लाख रह गयी"[2] शिक्षा में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन था यह अभियान आज भी "नीति आयोग द्वारा 2017–18 से 2019–20 के तीन वर्षीय एजेण्डे रिपोर्ट इण्डिया में एसी ही सिफारिश की गई है"(दैनिक जागरण, 25 दिसम्बर 2020) जिससे समग्र एवं किफायती शिक्षा मिल सके। वाजपेयी जी शिक्षा के प्रति अति जागरूक थे वह स्वयं शिक्षक बनना चाहते थे।

अटल जी स्वस्थ जनमानस के समुह को राष्ट्र की उन्नति का एक मजबूत आधार स्तम्भ माना रोगग्रस्त जन से मुक्त राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। अतः यह आवश्यक है कि जन स्वास्थ की बेहतर सुविधाए उपलब्ध करायी जाए। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए जो सर्वसुलभ एवं किफायती साबित होगा इस क्षेत्र में नये शोध को बढ़ावा देना चाहिए जिसके दूरगामी परिणाम लाभकारी सिद्ध होगे। अटल जी ने विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष की आलोचना करते हुए यह सुझाव दिया था।

सामाजिक रूढ़िया

सामाजिक समरसता के मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक पं. अटल बिहारी वाजपेयी जो अखण्ड भारत के स्वप्नद्रष्टा थे वह सदैव जाति प्रथा अस्पृश्य्ता जैसी प्रचलित कुप्रथाओ के विरोधी थे। यह भारत को आन्तरिक रूप से खोखला कर उसकी एकता की समृद्ध विरासत को नष्ट कर देगा। यहां तक की वेद एवं रामायण जैसे प्राचीन प्रमाण में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है जो गुण व कर्म पर आधारित है लेकिन अस्पृंश्यता का कही उल्लेख नही है। अटल जी स्वयं इस बात को मानते है उन्होंने कहा था, "अस्पृश्यता कानून के विरूद्ध नही है वह परमात्मा तथा मानवता के

1: Corresponding Author

विरूद्ध भी एक गम्भीर अपराध है।"(शर्मा 2018, पृ. 53) यदि हम इसे समाप्त न कर सके तो हम राष्ट्रीय एकता के मूल तत्व् को ही नष्ट कर देगे। सरकारी प्रयत्न ही पर्याप्त नहीं होते है वरन् उसके साथ जनसहयोग भी आवश्यक है। निःसन्देह आज देश प्रगति कर रहा है लेकिन अब भी सामाजिक रूढ़िया भेदभाव उसी रूप मे विद्यमान है। समाज को एक नये तरीके से चिन्तन करने की आवश्यकता है तथा संविधान में बने विधानों में समय–समय पर आवश्यक सुधार भी हुए लेकिन जागरूकता के अभाव में सामाजिक रूढ़िया अत्यन्त जड़ बन चुकी है। समाज में अब भी अश्पृश्यता, दहेज, बाल विवाह, कन्या शिशु हत्या, धार्मिक अन्ध विश्वास जैसी रूढ़िबद्ध धारणाएं कही छिपे तौर पर तो कही खुले तौर पर चल रही है। अटल जी समाज के इन छोटे मुद्दों के गम्भीर होते खतरे के प्रति समय–समय पर जनता को आगाह किया की सर्वत्र राजनीति करना उचित नहीं व नेताओं को मूल्यों की व आदर्शों की शिक्षा देने की बाते कही।

लोकतन्त्र

लोकतन्त्र को एक प्रकार मानने के बजाय भाव मानने वाले अटल जी ने लोकतन्त्र को सोच विचार, व्यवहार व जीवन बिताने का एक अभिन्न अंग माना। लोकतंत्र को समाजवाद से भी अधिक महत्व दिया। एक तरफ जहां पतन की ओर उन्मुख होते लोकतंत्र में मर्यादाएं टुटती जा रही है। सदन में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ऐसी परिस्थितियों को बनने से रोके, नेताओं का आचारण आदर्श बने भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जाए एक अन्य मुद्दा जिस पर अटल जी सर्वाधिक जोर देते थे वह था चुनाव की निष्पक्ष प्रक्रिया। कई स्थान ऐसे भी थे जहां चुनाव के समय मतदाता को डराया धमकाया जाता था और धनबल से प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता था, अतः यह सम्भव कैसे हो पाता की लोकतंत्र का एक मजबूत आधार जहां जनता अपनी पसन्द का चयन भी न कर सके वहा उपहास बनकर रह जाता है। इसमे द्विपक्षीय सुधार आवश्यनक है सरकार के स्तर पर एवं जनता के स्तर पर अतः आवश्यक है जनता के पास अपने प्रतिनिधि को उस दशा में वापस बुला लेना जब वह जनहित में कार्य न कर रहा हो।

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार शब्द अर्थ की दृष्टि से ही स्पष्ट है कि जो जीवन भ्रष्ट आचरण से निकल रहा हो और वही जीवन आगामी समय में एक व्यवस्था का निर्माण अवश्य करेगा। वाजपेयी जी भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए व्यक्तिगत जीवन को सुधारने पर बल दिया जिससे प्रशासन अच्छा बन सके। अतः अटल बिहारी जी ने लोकसभा में लोकपाल बिल पारित कराने का पूरा प्रयत्न किया जिसके दायरे में प्रधानमंत्री भी आते लेकिन सहयोग के अभाव में यह सम्भव नही हो सका। वह चाहते थे की जनहित के लिए सभी युवावर्ग अपने कर्तव्यो को समझे। स्वानमी विवेकानन्द के विचारो से प्रभावित अटल युवाओं को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग को आवश्यक बताया स्वयं भी अपने प्रधानमंत्री काल में शासन को भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शी बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम भी जनता को प्रदान किया। लेकिन जागरूकता के आभाव में अधिकार महत्वहीन हो जाते है। "यह हमारी व्यवस्था का दोष है। सामाजिक पिछड़ेपन का दोष है। जितने भी हम योग्य सुशिक्षित तथा सभ्य बनेंगे हमारा शासक भी उतना ही योग्य तथा विवेकी बनेगा या उससे ज्यादा।"(झा. 2004, पृ. 41) "लेकिन भ्रष्टाचार और वित्तीय धोखो ने युवाओं के लिए बहुत से अवांछनीय आदर्शो का निर्माण किया है।"(बेदी 2014 पृ. 14) अतः भारत के सन्दर्भ में लगातार ऐसी परिस्थितिया चाहिए जो नवजागृति की ओर उन्मुख हो।

जनलोकपाल बिल के प्रति अटल जी का प्रयास सराहनीय है कि, "प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी इस बात पर अडिग थे कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे के बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।"(शर्मा 2012, पृ. 18) अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सन् 1998 और 2001 में इसे पारित कराने का असफल प्रयास किया।

राजनीतिक विचार दर्शन

अटल जी मुलतः राजनीतिज्ञ थे उन्होंने सदैव शासन को एक आदर्श व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया जहां वे शासन को सुशासन का रूप देकर एक पारदर्शी उत्तरदायी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। अटल जी ने धर्म के आधार की जाने वाली राजनीति का विरोध किया क्योंकि सम्प्रदायिक आधार पर की गई राजनीति में भारत को खंडित होना पड़ा था यदि इस पर नियन्त्रण न किया जाए तो अन्य समस्याए भी नहीं सुलझ सकेगी जैसे राम मन्दिर, धारा 370, क्षेत्रवाद की बढ़ती भावनाएं और आतंकवाद जो वैश्विक समस्या बनी हुई है। कही न कही हमें अपने चिन्तन के परिपेक्ष्य को व्यापक करना होगा जिससे यह समस्याएं सुलझायी जा सके। राजनीति में भी सुधार करना अति आवश्यक है ताकि मूल्य परक राजनीति का स्वरूप बना रह सके। राजनीतिक परिपेक्ष्य में अटल जी के विचार द्रष्टव्य है जो अंकित है

सुशासन

पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में सुशासन की परम्परा को एक नया स्वरूप दिया। उन्हें भारत की शासन व्यवस्था को सम्भालने के जितने भी अवसर मिले उसका उन्होने पूर्णता के साथ सदुपयोग किया। उनके लिए राजनीतिक पद से महत्वपूर्ण था राजनीतिक व्ययवस्था में बदलाव आधुनिक होते भारत का औद्योगीकरण नगरीकरण के मध्य आवश्यकता होती है एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें राजनीतिक व प्रशासनिक वर्ग में कुशलता से समन्वय हो जहां पुलिस राज्य की तरह हुकुमत न हो वरन् कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके नागरिकों को समस्त सुविधायें उपलब्ध हो सके। यह व्यवस्था तभी सार्थकता से स्थापित हो सकेगी जब राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतन्त्र विद्यमान रहेगा और सत्ता के लिए समझौते नहीं होगे। सुशासन शब्द बहुत आकर्षक है और सुशासन की स्थापना के लिए भारतीय ही नहीं वरन् अनेक यूनानी धर्मग्रन्थों में कई प्रकार की व्यवस्थाओं के निर्माण की बाते कही गई है। मौर्यकाल के चाणक्य

यूनान के प्लेटो का आदर्श राज्य जहां ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में सत्ता की जिम्मेादारी देने की बात कही गयी है। भारतीय जातक कथाएं नीतिसार अष्टाध्यायी आदि भारतीय ग्रन्थों में सुशासन की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। इन्ही ग्रन्थों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अटल बिहारी ने सुशासन की नीव रखी। अतः अटल बिहारी सदा से मूल्ययुक्त परिवेश के निर्माण पर जोर देते रहे। "राज्य सरकार और प्रशासन का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि राज्य कैसा है, सरकार और प्रशासन का स्वरूप कैसा है? क्या् इसे 'अच्छी सरकार' अथवा सुशासन अथवा अभिशासन कहा जा सकता है, प्राचीन काल में सुशासन को आदर्श राज्य अथवा राम राज्य की अवधारणा के परिपेक्ष्यओं में परिभाषित किया गया है।"(फड़िया 2015 पृ. 915) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट" उल्लेखित है कि "सभी सार्वजनिक पदो पर आसीन व्यक्ति जनता की धरोहर है। सरकारी भूमिका में वृद्धि से सार्वजनिक पद पर बने लोग जन–जीवन पर पर्याप्त प्रभाव डालते है। जनता और पदाधिकारी के बीच में धरोहर का सम्बन्ध यह अपेक्षा करता है कि अधिकारियों को सौंपे गए अधिकारो का प्रयोग लोगों की सर्वोत्तम भलाई या जनहित में किया जाना चाहिए।"(द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग,जनवरी 2007 पृ. 19)

व्यवस्था के आरम्भ से लेकर सभी काल खण्ड में प्रशासन का आधार सुशासन की संकल्पना पर ही केन्द्रित रहा है अटल जी इस तथ्य से भलीभाँति अवगत थे कि शासन को सुशासन के रूप में संचालित करना जनता के प्रतिनिधि का नैतिक दायित्व है अतः एक प्रतिबद्ध व्यवथा्पक हो जो कानून के अनुसार कार्य करे उसके कार्यो में पारदर्शिता हो, उनका निष्पक्ष निष्पादन हो क्रियान्वयन हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो अर्थात पूछे गये प्रश्नो् का उचित उत्तर मिले प्रशासन से सरकार को सेवा प्रदाता की तरह जन केन्द्रित व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। जहां लोग स्वयं को शासन से अलग न समझे और अपना पूर्ण सहयोग करे। बदलते परिदृश्य के साथ ही प्रशासन को बदलाव का वाहक बनना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियां नित नवीन रूप में सामने आ रही है और राष्ट्र के आत्मनिर्भर विकास में दक्ष सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो व्यक्तिगत प्रभावों से दूर निष्पक्ष तरीके से कार्य करते है बशर्ते उन पर कोई राजनीतिक दबाव न हो। इन दुष्प्रभावो से बचने के लिए भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गयी है जिसके द्वारा लोक केन्द्रित प्रशासन को मूर्तरूप दिया जा सकता है।

साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता एक ऐसी खतरनाक मनोवृति है जहा लोग राष्ट्रहित के बजाय व्यक्तिगत हित को महत्व देने लगते है। पं. अटल बिहारी भारतीय राजनीति को सम्प्रदायवाद के जहर से मुक्ति रखने के लिए प्रयत्नशील थे। विभिन्न धर्मो के मध्य एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया क्योंकि धर्म सम्प्रदाय के आधार पर यदि अलगाव की भावना आ जाए तो उसे बदलना बहुत ही मुश्किल होती है।

अटल जी ने लोकसभा में अपना पक्ष रखते हुए साम्प्रदायिक होते वातावरण पर कहा था कि "अगर आप वास्तव में सम्प्रदायवाद को पनपने नहीं देना चाहते तो साम्प्रदायिकता फिर कैसी भी हो उससे अपको लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए अन्यंथा साम्प्रदायिकता का निर्मूलन नही हो सकता।"(घटावे 2014 पृ.496) अटल जी इसमे सभी पक्षों का सहयोग लेना चाहते थे जहां लोग अपने क्षूद्र स्वार्थ का त्याग करे और राजनीतिक लाभ लेना बन्द कर दे। भारत एक राष्ट्र है। "राष्ट्र मनुष्य जाति का एक ऐसा भाग है जो दूसरो के प्रति सहानुभूति से बंधा हुआ एक सरकार के अधीन रहने की प्रबल इच्छा रखता हो।"(नारायण, 1993 पृ.263) आज की विविधतापूर्ण परिस्थिति में उस पहचान का संकट है। संघर्षो को टालने की जिम्मेदारी भी उसी पर है जिसे जगत ने अपना प्रतिनिधि चुना है।यदि वही अपने दायित्व भूल बैठेंगे तो परिस्थितियां और विकट हो जाएगी। भारत का विभाजन भी इन्ही आधारों पर हुआ हैं।

राम मन्दिर

राम मन्दिर भारत की आस्था का मुद्दा है उसके साथ कई पीढ़ियों का विश्वास जुड़ा हुआ है यदि विश्वास के साथ खेल होगा जन भावनाओं को आहत किया जाएगा उन परिस्थितियों में जो परिणाम प्राप्त होंगे उनके जिम्मेदारी सिर्फ तत्कालीन सरकार की होगी। कोई भी घटना स्वयं नहीं घटित होती है वरन् उसका कारण उसके मूल में ही छिपा रहता है प्रत्येक आम भारतीय व्यक्ति धर्म के प्रति सदभावपूर्ण है लेकिन बात जब उसके आराध्य देव की आती है जिनके प्रति वे युगो से समर्पित है व धैर्य धारण किये हुए है व सदभाव की स्थापना के लिए उन्हे की जन्मभूमि पर उन्हे ही आस्था दिलाने के लिए इतना लम्बा संघर्ष करना पड़ेगा जिसके लिए सबुतों की भी कमी नही है न ही गवाहों की तत्क़ालीन इतिहास के पन्ने स्वयं इस बात के गवाह है कि मर्यादा पुरूषोत्तम राम सदा से अयोध्या की धरती पर विराजमान रहे है। यदि आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि कारसेवकों ने मन्दिर के ऊपर हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। इसके पीछे उनका एक लम्बा. आश्वासन था जो लगातार दिया जा रहा था लेकिन पूरा नहीं हो रहा था। जनता पुनः एक हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट मे ले गयी। जब 1999 में अटल जी की सरकार बनी उन्होंने पूरा प्रयत्न किया कि मामले का शान्तिपूर्ण हल निकाला जाए दोनों पक्ष आपसी सहमति पर आये लेकिन विवाद हल न हो सका। साम्प्रदायिकता को भड़का कर पुनः दंगे करा दिये जाने की सम्भावना बढ़ती जा रही थी लेकिन समाधान की कोई सम्भावना न बन सकी। "स्वतन्त्रता के बाद भी दशको तक अनसुलझा रहा अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद आखिरकार नौ नबम्बर 2019 को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद समाप्त हो गया। 130 साल से चले आ रहे इस संवेदनशील मामले पर परदा गिर गया।"(दैनिक जागरण वाराणसी 11 नवम्बर 2019) अटल जी इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनका एक स्वप्न, पूर्ण हो गया। धारा 370 जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहा लेकिन संविधान निर्माण के समय अस्थामयी उपबन्ध् का प्रावधान कर धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा प्रदान कर उसे सम्पूर्ण भारत से अलग कर दिया गया। जनता को यह भेदमूलक

संवैधानिक व्यवस्था रास न आयी और सम्पूर्ण जनता की आवाज बनकर उभरे डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोकसभा में आवाज उठायी और धारा 370 के समाप्ति की मांग की उन्होंने माँग पूरी न होने पर बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने की कोशिश की और वहां जाने के बाद वे जीवित न आ सके। इस घटना से आहत अटल जी ने कहा था "कश्मीर घाटी से तीन लाख हिन्दू निकाल दिये गये। कश्मीरी हिन्दूओं का निष्कासन मानव अधिकारों का गम्भीर उल्लंघन है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वह नारा बार–बार दोहराया है कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान व एक देश में दो निशान नहीं चलेगे।"(गुप्त, 1999, पृ. 183) अनुच्छेद 370 हटाना अति आवश्याक है। इस ऐतिहासिक भूल का सुधार 5 अगस्त 2019 को हुआ जब धारा 370 समाप्त हुआ। "अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बजाए सरकार ने इसी अनुच्छेद के खंड तीन द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्ति का उपयोग करके इसे निष्क्रिय कर दिया।"(दैनिक जागरण, वाराणसी, 6 अगस्त 2019)

क्षेत्रवाद

क्षेत्रवाद जैसी संकीर्ण मनोवृत्ति जहां व्यक्तियों का एक छोटा समूह सर्वहित सोचने के बजाय अपने क्षेत्रीय हित को प्राथमिकता प्रदान करता है। भारत विविधता वाला देश है जिसे संकीर्ण स्वा्र्थ से परे चिन्तन करके ही स्थिर रखा जा सकता है। भारत के कई राज्यों में धर्म, भाषा जाति सम्प्रदाय आदि के आधार पर अलग से मान्यता प्रदान की जाए उन पर अन्य कोई भाषा न थोपी जाए यहां तक की मातृभाषा हिन्दी भी नही। जिस भी राष्ट्र में जनता अपने क्षुद्र स्वार्थो के लिए प्रयासरत रहेगी कि धर्म जाति भाषा के आधार पर उसकी मांगे पूरी की जाए। वह राष्ट्र अलगावाद साम्प्रदायिकता एवं रूढ़िवादिता से पूर्णतया घिर जाएगा। अटल जी की कही गयी बाते आज कई मायनों में स्पष्ट रूप से सही साबित हो रही है। देश में हर वर्ग अपने धर्म जाति एवं स्वार्थ के अनुसार सरकार पर मांगे थोप रहा है और उन्हें पूरा करवाने के लिए आन्दोलन व धरना प्रदर्शन कर सामान्यं जन जीवन तक को बाधित कर रहा है साथ ही अनावश्यंक तोड़–फोड़ सरकारी सम्पति को नुकासान पहुँचाना उनका सामान्य कार्य बन गया है। इन संघर्षों का फायदा सभी क्षेत्रीय दबाव समुह अपना हित साधने में कर रहे है। सामाजिक समरसता सौहार्द की बाते मात्र दिखावा भर ही रह गयी है। लोकतन्त्र को लगातार आघात पहुँचाया जा रहा है और राष्ट्रीय एकीकरण से पहले ही संकीर्ण मानसिकता के कारण क्षेत्रियतावाद की भावना अत्यन्त प्रबल होती जा रही है।

राजनीतिक मूल्यो का अवमूल्यन

पं0 अटल बिहारी वाजपेयी का समस्त जीवन राजनीति में एक आदर्श रहा वे अपने सिद्धान्तो एवं प्रतिबद्धताओ के प्रति सदैव समर्पित रहे। राजनीति का बदलता स्वरूप अटल जी को विचलित कर देता था राजनीति में मूल्यों का अवमूल्य न हो रहा राजनीति में हमेशा से सत्ता की चमक के आगे राजनेताओं के चेहरे और भाषा बदल जाती है लेकिन अटल जी कितने भी ऊँचे पद पर रहे उनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा। सदन से जुड़ा एक वाकया था जब राजा जौनपुर श्री यादवेन्द्रज दत्त जी को अपनी बात रखनी थी सीमित समय में उस वक्त् अटल बिहारी वाजपेयी व लालकृष्णी आडवाणी ने अपनी भी समय उन्हो दे दिया। अटल जी अपनी मूल्यपरक राजनीति के लिए सदैव लोगो के द्वारा याद किये जाते है। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनके लिए उँचे पद का महत्व नहीं था वरन् उस पर बैठे व्यक्तित्व का गुण महत्व पूर्ण था। अतः अटल जी ने मूल्यपरक राजनीति पर अपनी बाते कही व सदन के बदलते आचरण पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उनके द्वारा अपने फायदे के लिए दल बदल करना सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए पैसे का प्रलोभन देना तथा सत्ताक पक्ष द्वारा अपनी आलोचना होने पर सदन की कार्यवाही को स्थागित करना या बाधा पहुँचाना आदि पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही तथा स्वयं को इनके विपरित आदर्श रूप में प्रस्तुकत किया। अटल जी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों से स्पष्ट है कि विविधता युक्त देश में आदर्श राजनीतिक परिदृश्य का निर्माण साफ सुथरी सामाजिक पृष्टभूमि पर ही किया जा सकता है। अनेक अवसरो पर अटल जी ने ऐसे साहसिक विचार प्रस्तुत किये एवं निर्णय लिये जो आज भी मिसाल है। अपने सामाजिक एवं राजनीतिक विचारो में जिस प्रकार अटल जी ने स्वाास्थ्य शिक्षा रूढ़ियां, लोकतन्त्र भ्रष्टाचार, सुशासन, साम्प्रदायिकता, राम मन्दिर, धारा 370, आतंकवाद आदि विषयों पर जो विचार दिया है, वह आज भी उतने ही उपयोगी एवं सार्थक है जितने तत्काालीन समय में थे।

REFERENCES

झा.सी.एम (.2004) *भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान,* राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड

बेदी किरण,(2014) *भ्रष्टाचार भारत छोड़ो,* प्रभात प्रकाशन दिल्ली संस्करण

धाकरे अलका सिंह (2018), *भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी* अनुराग प्रकाशन,संस्करण

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग चौथी रिपोर्ट शासन में नैतिकता जनवरी 2007

शर्मा महेश,(2015) *प्रखर राष्ट्र वादी राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी,* डायमंड पाकेट बुक्स संस्करण

शर्मा चन्द्रिका प्रसाद (2018) *कुछ लेख कुछ भाषण अटल बिहारी वाजपेयी,* घर प्रकाशन, संस्करण

नारायण, इकबाल (1993) *राजनीतिशास्त्र के मूल सिद्धान्त* रतन प्रकाशन मन्दिर संस्करण

गुप्त राधेश्याम (1999) *निष्काम कर्मयोगी अटल बिहारी वाजपेयी* दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रकाशन, प्रथम संस्करण